

शर्यहाश दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-29 अंक-24

23 दिसम्बर, 2014 से 6 जनवरी, 2015

मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

मूल्य : 2 रुपये

पेशावर में बच्चों के दर्दनाक हत्याकाण्ड पर शोक जुलूस



नई दिल्ली : 16 दिसम्बर 2014 को विश्व इतिहास में घटी एक हृदयविदारक और भयावह घटना जिसमें पाकिस्तान के पेशावर में 132 स्कूली छात्रों और 9 कर्मचारियों की तालिबान द्वारा किए गए एक आतंकी हमले में हत्या कर दी गई। इसके विरोध में 17 दिसम्बर को जंतर-मंतर पर एआईडीएसओ और एआईएमएसएस के संयुक्त तत्वावधान में शोक वेदी पर पुष्पांजली अर्पित कर मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। इसमें शामिल छात्र-छात्राओं और महिलाओं ने मासूम बच्चों पर बर्बर हमले के विरोध में 'आतंकवाद मुर्दाबाद', 'धार्मिक कट्टरतावाद मुर्दाबाद', 'मासूमों के हत्यारे तालिबान मुर्दाबाद', 'मानवता के शत्रु धार्मिक कट्टरतावाद को परास्त करो', 'आतंकवाद का सरगना अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद' आदि नारे लगाये।

संगठनों के नेताओं ने कहा कि तालिबान उग्रपंथियों ने लम्बे समय से न केवल पाकिस्तान में बल्कि भारत सहित पूरे विश्व में जनवादी शिक्षा का विरोध किया है। इन्होंने पुनर्जागरण के विचारों का विरोध करते हुए धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और मध्ययुगीन कुसंस्कारों को फैलाने का काम किया है। इन्होंने इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा है तथा विज्ञान और इतिहास में पौराणिक कल्पित कथाओं को मिलाकर पेश किया है।

मृतकों के प्रति गहरा दुख प्रकट किया गया और जनता से इस घटना का स्वतःस्फूर्त ढंग से विरोध करने की अपील की गई। 18 दिसम्बर को पूरे देश में अखिल भारतीय शोक दिवस मनाने का ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऐलान भी किया गया।

तालिबानों द्वारा किये गये पेशावर के क्रूर हत्याकाण्ड की एसयूसीआई(सी) ने की निन्दा

कट्टरपंथी-आतंकवादियों की इस बर्बरता को रोकने के लिए साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन तेज करने की लोगों से की अपील

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 17 दिसम्बर को जारी बयान में कहा :

यह पाशविकता अक्षम्य है। क्रूर भीषणता के साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसे आतंकी हमलों और निर्मम हत्याओं को अंजाम दे रहे कट्टरपंथी तहरीक-ए-तालिबान के हथियारबंद हत्यारों द्वारा पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के 140 मासूम छात्रों की निर्मम हत्या की निन्दा करने लायक शब्द हमारे पास नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि तमाम प्रगतिशील जनवादी आन्दोलनों और लोगों के तार्किक मन को तबाह करने के लिए तालिबानों समेत तमाम धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों को एक समय साम्राज्यवादियों, खास कर अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किया गया, पाला पोसा गया और इस्तेमाल किया गया। तालिबानों समेत वे तमाम जिनको अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने अपने षृणित प्रभुत्ववादी स्वार्थ और अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर गुंडागर्दी को पुख्ता करने के लिए पाला पोसा था, अब बेहद खौफनाक आतंकवादियों और मौत के सौदागरों के रूप में उभरे हैं जो अपनी ताकत का दिखावा करने के लिए मध्ययुगीन बर्बरता से भी बदतर और जान लेवा हिंसा बरपा रहे हैं, नरसंहार रच रहे हैं और कारगराना ढंग से निर्दोष लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को निशाना बना रहे हैं। दरअसल, इन धार्मिक कट्टरपंथियों और ऊधमी हत्यारों का कोई मजहब नहीं होता, कोई देश

नहीं होता, इनको इनसान कहलाने तक का हक हासिल नहीं है। मानवजाति को बंधक बनाने और निहित स्वार्थों की अधीनता में हत्याकाण्ड की धूम मचा कर खुश करने के लिए इनको प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा पैदा किया गया है। लाजिमी है कि इन खूखार ताकतों से सख्ती से निपटा जाए और लोगों से पूरी तरह इन्हें अलग-थलग कर दिया जाए। लेकिन पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देशों के शासक इन रक्त-पिपासू ताकतों से लोगों की रक्षा करने में नाकाम हो रहे हैं। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सरकार भी इन बर्बर ताकतों के चंगुल से लोगों को निजात दिलाने की बजाय इनके प्रति नरमी बरत रही है और इस तरह दरअसल एक ऐसे कारगराना हत्याकाण्ड को अंजाम देने के उनके लिए इसने अवसर पैदा कर दिये।

शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए हम दुनिया भर के लोगों का आह्वान करते हैं कि वे नस्ल, धर्म, इलाके या वंशमूल की भावना से ऊपर उठ कर अपनी एकता को पक्का करें, सड़कों पर उतर आये, साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन तेज करें और तालिबानों और उन जैसों की, चाहे वे किसी भी जगह के हों, कोई भी भाषा बोलते हों और किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनकी ताण्डव लीला को रोकने के लिए कट्टरपंथी सिद्धांतों के खिलाफ एक जबरदस्त वैचारिक संघर्ष छेड़ दें।



पेशावर में तालिबानों द्वारा मारे गये मासूम बच्चों को श्रद्धांजली देते हुए दिल्ली में 18 दिसम्बर को जंतरमंतर पर एसयूसीआई(सी) कार्यकर्ता

सस्कार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर में वामपंथी पार्टियों के धरने-प्रदर्शन

केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों, आसमान छूती महंगाई, साम्प्रदायिकता, मनरेगा में कटौती, नई भरतियों पर रोक, किसानों की फसल के लाभकारी मूल्य तक न मिलना, महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व हिंसा की घटनाओं में इजाफा, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों, श्रम कानूनों में मालिकपरस्त संशोधनों, धर्मनिरपेक्षता तथा समाज की साझी विरासत-साझी संस्कृति को मटियामेट कर मेहनतकश जनता को भातृघाती दगे-फसादों में फंसाने की साजिश आदि के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई (एमएल)-लिबरेशन, आरएसपी, फरिबर्ड ब्लॉक इत्यादि देश के छह प्रमुख वामपंथी दलों ने दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में देशव्यापी संयुक्त आंदोलन चलाने का फैसला लिया। इस फैसले के तहत देश भर में धरने-प्रदर्शन हुए।

दिल्ली : इस कार्यक्रम के तहत सीपीआई(एम), एसयूसीआई(सी), सीपीआई, सीपीआई(एमएल) लिबरेशन, फारवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के संयुक्त आह्वान पर हजारों लोगों ने 13 दिसम्बर को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। (शेष पृष्ठ 6 पर)



दिल्ली

दिल्ली में प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल

मोदी सरकार द्वारा नई भर्तियों पर रोक, दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा, महिलाओं व बच्चों पर बढ़ते अपराध और युवाओं की अन्य समस्याओं को बढ़ाने के खिलाफ धरना

दिल्ली : 10 दिसम्बर को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) की दिल्ली राज्य कमेटी की ओर से मोदी सरकार द्वारा नई भर्तियों पर रोक, दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा, महिलाओं व बच्चों पर बढ़ते अपराध तथा सरकार द्वारा बेरोजगारी, महंगाई, नशाखोरी व अश्लीलता को बढ़ावा देने के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया गया। संगठन की ओर से केन्द्र सरकार तथा डीजीईटी को मांगों का एक ज्ञापन भी दिया गया। जिसका नेतृत्व संगठन के कोषाध्यक्ष इंद्रदेव ने किया। धरने में दिल्ली के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों नौजवानों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया जो हाथों में मांग लिखित पट्टिकाएं लिये हुए थे।

धरने को एआईडीवाईओ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार, एसयूसीआई(सी) दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य हरीश त्यागी, दिल्ली राज्य अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार, उपाध्यक्ष डॉ. गिरिश कुमार, सचिव डॉ. प्रकाश देवी के अलावा कॉमरेडस इंद्रदेव, प्रभाष, रामबदन, अमरजीत, नवीन, रीतु अस्वाल आदि ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले लोगों को अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक पर एक जनविरोधी नीतियों को लागू कर रही है। नौजवानों को नौकरियां देने की बजाए नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। महिलाओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े वादे किये थे मगर दिल्ली में महिलाओं व बच्चों पर हमले बढ़ गये हैं। उनकी सुरक्षा के लिए नये इंतजाम करने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। प्रचार माध्यमों से अश्लीलता फैलाई जा रही है मगर खुद को



दिल्ली में जंतर मंतर पर हुई धरना सभा को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड हरीश त्यागी

ऊँची संस्कृति का झंडाबरदार बताने वाली भाजपा सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। दिल्ली में एक पर एक साम्प्रदायिक घटनाएं हो रही हैं। अभी चर्च पर भी हमले हुए हैं। मगर अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। चुनाव से पहले यह दिल्ली के माहौल को खराब करने की किसी साजिश का भाग लगती है। धर्म के नाम पर दंगे फैलाने वाले तत्वों का भी वक्ताओं ने जोरदार विरोध जताया तथा सरकार से मांग की कि हाल ही दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीति का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि रेल भाड़ा वृद्धि के माध्यम से सरकार ने सभी आवश्यक वस्तुओं के दामों को बढ़ाने का काम किया है। सब्जियों के दाम, चीनी, दूध सहित रोजाना की सभी वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं। नौजवानों के बीच नशाखोरी को बढ़ावा देने की

नीति का भी विरोध किया गया और सरकार से मांग की कि वह नशाखोरी को रोकने के लिए शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबंध लगाए। नशाखोरी और अश्लीलता अपराध की मुख्य जड़ है। सरकार को इस पर रोक के साथ-साथ अश्लीलता फैलाने वाले माध्यमों पर भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही वक्ताओं ने आई.टी.आई. में सेमेस्टर प्रणाली का भी विरोध किया तथा सरकार से सेमेस्टर प्रणाली को तुरंत वापस लेने तथा आईटीआई के सभी प्रशिक्षुओं को 50 की जगह 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की मांग की।

वक्ताओं ने नौजवानों का आह्वान करते हुए कहा कि नौजवान आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याओं से घिरा हुआ है वह महंगाई, बेरोजगारी तथा गरीबी की दलदल में धंसता चला जा रहा है तब इन परिस्थितियों में आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। धरने का संचालन संगठन के कार्यालय सचिव प्रभाष ने किया।

शराब की दुकान एवं बार बंद करने की उठी मांग

दुर्ग (छ.ग.) : एस.यूसी.आई.(कम्युनिस्ट) जिला संगठन समिति दुर्ग के द्वारा तितुरडीह में वार्ड 19 कैलाश नगर, उडिपापाप, आदित्य नगर व सिंधिया नगर, हनुमान नगर, मुकुट नगर के बीचों बीच मोहल्ले से लगती हुई तितुरडीह शराब की दुकान व शहीद भगत सिंह स्कूल के सामने का बार हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान और आंदोलन जारी है।

ज्ञात हो कि तितुरडीह शराब की दुकान के कारण मोहल्ले में मारपीट, लड़ाई झगड़े, चोरी, लूटपात, पारिवारिक झगड़े, छेड़खानी होना आम बात हो गई है। आये दिन इस प्रकार की घटनाओं से मोहल्ले में अशांति व तनाव रहता है। चूँकि मोहल्ले में लड़कियों एवं महिलाओं का स्कूल-कॉलेज, अस्पताल एवं जरूरी कामों के लिए बाहर आना-जाना लगा रहता है यह शराब की दुकान एवं बार इसी रास्ते में है जिसके कारण वे डरी-सहमी सी यहाँ से गुजरती हैं। घर वाले भी शर्म होते ही चिंतित होने लग जाते हैं जब तक कि वे सही सलामत घर न पहुँच जायें और हमेशा कोई अनहोनी का डर लगा रहता है। सड़क पर चलते लोग डरते रहते हैं कि कोई उन्हें रोककर उनका मोबाइल व रुपये आदि न छीन ले। इसी प्रकार इस बार के कारण स्कूल एवं मार्केट के आसपास का माहौल खराब हो रहा है। स्कूली बच्चों को शराब एवं नशे की लत पड़ रही है। इस बार एवं शराब की दुकान के कारण लड़कियों की संख्या स्कूल में कम हो रही है।

किसान व खेत-मजदूरों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन

जौनपुर (उ.प्र.) : ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन की जौनपुर जिला कमेटी के द्वारा 29 अक्टूबर को किसान व खेत मजदूरों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया गया। इसके पहले जौनपुर मिनी रेलवे स्टेशन से रैली निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जिला मुख्यालय पहुँचकर धरना सभा में तब्दील हो गई।

धरने पर बिजली के दाम कम करने, विद्युत अनापूर्ति समस्या हल करने, कृषि योग्य भूमि का अधिगृहण बन्द करने, सड़क बाईपास योजना रद्द करने, कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त धांधली व भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, फसलों की जंगली जानवरों से रक्षा करने, नहरों में पानी छोड़ने, खाद उपलब्ध कराने, महंगाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व काला धन पर रोक लगाने इत्यादि के बाबत आवाज बुलन्द की



समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन करते हुए किसान-खेत मजदूर

गई। सभा की अध्यक्षता एआईकेकेएमएस के जौनपुर जिला अध्यक्ष डॉ. श्रीपति सिंह व संचालन मिथिलेश मौर्य ने किया। सभा को डॉ. प्रवीण कुमार शुक्ल, राजबहादुर मौर्य, जयप्रकाश पाण्डेय, हीरालाल गुप्त, लालता प्रसाद मौर्य इत्यादि ने सम्बोधित किया। अन्त में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सम्बोधित 13 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी जौनपुर को सौंपा गया।

पानी सप्लाई देने की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय तक जूलूस निकाला



दुर्ग छ.ग. : यहां मीलपारा की महिलाओं ने एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) जिला दुर्ग छ.ग. के नेतृत्व में 7 नवम्बर को पानी सप्लाई व मोहल्ले की अन्य समस्याओं के खिलाफ मोहल्ले से नगर निगम कार्यालय तक जूलूस निकाला और जोरदार प्रदर्शन कर कमिश्नर के समक्ष अपनी मांगें रखी। यहाँ साल भर सार्वजनिक व घरेलू नलों में पानी नहीं आता व महिलाएं यहाँ वहाँ से पानी की जरूरत पूरी करती हैं। इसके कारण महिलाएं आक्रोशित हैं। इसके खिलाफ पिछली गर्मी के मौसम से लगातार आंदोलन चल रहा है किन्तु समाधान नहीं किया गया है।

लालगंज (बिहार) में किसानों का रोष प्रदर्शन

सभी जरूरतमंदों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड, उपलब्ध कराने, नकली खाद-बीज व कीटनाशक दवा की हो रही बिक्री रोकवाने, राशन-किरोसिन की कालाबाजारी बन्द करने और निर्धारित दर मात्रा से वितरण कराने, रेफरल अस्पताल में महिला एवं पुरुष डाक्टरों द्वारा यात्री सेवा बहाल कराने, लालगंज से सभी रूटों का बस व टेम्पो भाड़ा प्रति किलोमीटर तय करने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, जैसी ज्वलंत मांगों को लेकर केकेएमएस ने 18 नवम्बर को गण्डक प्रोजेक्ट मैदान से जूलूस निकाला गया। संगठन के वैशाली जिला संयोजक डॉ. राजेन्द्र शर्मा एवं प्रखण्ड सचिव डॉ. महेश पासवान ने इसका नेतृत्व किया।

यह दफ्तर क्रान्ति के प्राणकेन्द्र के तौर पर काम करेगा

नवनिर्मित केन्द्रीय कार्यालय के उद्घाटन पर कॉमरेड प्रभाष घोष

कोलकाता : इन्तजार बहुत दिनों से था। देशभर में पार्टी कार्यकर्ता-समर्थक इंतजार कर रहे थे कब नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन होगा। पुराने जर्जर हो गये कार्यालय की इमारत के टूटने से थोड़ा-थोड़ा करके जितना तैयार हो रहा था उतना राज्य और शहर के लोग जो उस रास्ते से आया जाया करते थे, गांव-कस्बों में रास्तों और रेलों में इस भवन के लिए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ताओं की अपील के जवाब में जिन्होंने चंदा दिया था, वे सभी उत्सुक थे कि आखिर कब एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) का अपने दफ्तर के भवन का उद्घाटन होगा। इसलिए महान नवम्बर क्रान्ति की याद में 17 नवम्बर को उद्घाटन का दिन तय होने के बाद ही नाना उपायों से यह जानकारी दे दी गई।

17 नवम्बर को दोपहर 12 बजे जब झण्डा फहराने के जरिये संक्षिप्त उद्घाटन समारोह शुरू हुआ तो 48 लेनिन सरणी के सामने दोनों तरफ के फुटपाथ पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व हमदर्दों की मौजूदगी से ठसाठस भर गये थे। कितने ही वरिष्ठ नेता-कार्यकर्ता जिनकी उम्र और रोग के भार से जो अब लगभग चल-फिर नहीं सकते हैं, वे भी इस समारोह में कार्यकर्ताओं की मदद से झुके हुए शरीर के साथ धीरे-धीरे आ बैठे थे। केवल नये लोगों के ही नहीं, बल्कि बुजुर्गों के चेहरे-मोहरे, बातों में था आवेग और उत्साह का प्रबल उत्ताप। 'हमारी पार्टी का अपना भवन बन गया है, यह तो हमारा ही भवन है'—यही थी सब के दिल की बात।

दोपहर 12 बजे कॉमरेड प्रभाष घोष ने लाल झण्डा फहराया। कॉमरेड लेनिन और शिवदास घोष की तस्वीरों पर पोलिट ब्यूरो सदस्यगण कॉमरेड रणजीत धर, माणिक मुखर्जी, असित भट्टाचार्य ने एक-एक करके माल्यार्पण किया। अस्वस्थ कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्य सचिवमण्डल के सदस्य कॉमरेड तपन रायचौधरी ने माल्यार्पण किया। इसके बाद केन्द्रीय कमटी सदस्यों कॉमरेड देवप्रसाद सरकार, शंकर साहा, छाया मुखर्जी, सी.के. लुकोस, सौमेन बसु, के. राधाकृष्ण, सत्यवान, गोपाल कुण्डु ने माल्यार्पण किया। दिल्ली से लेकर अन्दमान तक लगभग सभी राज्यों के सचिवों अथवा प्रतिनिधियों और जनसंगठनों के सर्वभारतीय नेतागण ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजली दी।

नवनिर्मित भवन की चौथी मंजिल पर लगाई गई थी कॉमरेड शिवदास घोष द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों की एक प्रदर्शनी, जिसने कॉमरेडों के हृदय के भवावेग को मथ डाला।

उद्घाटन के अवसर पर कॉमरेड प्रभाष घोष ने कहा कि आज 17 नवम्बर है। महान मार्क्स-एंगेल्स के वैज्ञानिक समाजवाद की विचारधारा का सार्थक प्रयोग करके महान लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में रूस की सरजमीन पर

मजदूर वर्ग ने पूँजीवादी और हर तरह के शोषण को उखाड़ फेंक कर समाजवाद कायम करने के लिए जो संघर्ष संगठित किया था, 1917 में इसी 17 नवम्बर को यह संघर्ष सफलतामण्डित हुआ था। मानव इतिहास में, रवीन्द्रनाथ के शब्दों में, नये युग की शुरूआत हुई थी।

इस नई सभ्यता को दुनिया के मजदूर वर्ग, शोषित जनता, आजादी आन्दोलन में जिन्होंने देश-देश में लड़ाई लड़ी उन सभी ने इसका अभिनन्दन किया, नये भरोसे के रूप में देखा। यूरोप के उस समय के श्रेष्ठ मनीषी रोमां रोलॉ, बर्नॉड शा, आइन्स्टाइन, सभी ने समाजवादी सभ्यता का स्वागत किया था, उसके पक्षधर थे। हमारे देश के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, रवीन्द्रनाथ, शरतचन्द्र, नजरूल, प्रेमचन्द, भगत सिंह सहित सभी ने समाजवादी सभ्यता का नये सूर्योदय के तौर पर वरण किया था। यह सब इतिहास में लिपिबद्ध है। यह समाजवाद महान स्टालिन के नेतृत्व में दुर्जेय शक्ति में तब्दील हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय, आप जानते हैं कि अगर स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने ऐतिहासिक भूमिका नहीं निभाई होती तो फासिस्ट जर्मनी-इटली-जापान की हार ही नहीं होती। हर उपनिवेश अर्धउपनिवेश के मुक्ति-संग्राम में भी सोवियत संघ ने हर तरह की मदद दी थी। फिर



यह भी अफसोस की बात है कि लम्बे अरसे तक चलने के बाद साम्राज्यवाद-पूँजीवाद की साजिश और रूस की अन्दरूनी प्रतिक्रान्तिकारी ताकतों, संशोधनवादियों की साजिश से सोवियत समाजवाद ढह गया, और पूरी दुनिया में-रोमां रोलॉ के शब्दों में कहें तो एक अंधकार युग छा गया-जो अंधकार आज हम देख रहे हैं। हालाँकि हम यह भी जानते हैं कि यह अन्तिम बात नहीं है। दुनिया में कोई भी बड़ा आन्दोलन सैकड़ों साल लड़ाई के बिना मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। जो 'ईश्वर की शक्ति बड़ी बलवान होती है' दावे के साथ यह कहा करते हैं, उस धार्मिक आन्दोलन की जद्दोजहद को भी सैकड़ों साल तक हार-जीत की राह पर चलना पड़ा। बुजुर्ग आ जनतांत्रिक क्रान्ति को भी साढ़े तीन सौ साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हालाँकि ये सभी लड़ाइयाँ और क्रान्तियाँ शोषण के खात्मे की लड़ाइयाँ नहीं थीं। सोवियत समाजवाद को दासप्रथा, सामंतवाद, पूँजीवाद के हजारों साल के इतिहास के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। इसके बावजूद अस्सी साल सिर ऊंचा किये खड़ा रहा।

पूरी दुनिया की जनता के साथ आज हमारे देश की जनता भी मुक्ति चाहती है, आन्दोलन चाहती है, लेकिन रास्ता उन्हें मालूम नहीं है। वह रास्ता उन्हें नवम्बर क्रान्ति दिखा सकती है। हमारे देश में महान मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग के सुयोग्य उत्तराधिकारी और अनुगामी सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के नेतृत्व में कायम एकमात्र साम्यवादी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) ही लम्बे अरसे से नवम्बर क्रान्ति के झण्डे को उठा कर चल रही है।

हमने आज ऐतिहासिक 17 नवम्बर को हमारी पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन का दिन तय किया। पुराने कॉमरेड जो अब अब बूढ़े हो गये हैं, जिन्होंने कॉमरेड शिवदास घोष को देखा है, उनके कई मूल्यवान भाषण सुने हैं। उन्होंने सुना है कि कितने कठिन और कड़े संघर्ष के जरिये उन्होंने एक दिन इस पार्टी को गठित किया था। वह मैं अपने शब्दों में कहना नहीं चाहता हूँ, 1969 में उन्होंने एक चर्चा में जो कहा था, मैं यहाँ उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। कॉमरेड शिवदास घोष उस 1944, 45, 46, 47 से 50, 51 में जो कठिन

संघर्ष किया था यह उस संघर्ष के दिनों को याद करा देगा। वे कह रहे हैं, "मैंने अपने जीवन में ही देखा कि पहले जब हमने पार्टी-गठन का काम शुरू किया था उस समय ज्यादा समर्थक नहीं थे, यहाँ तक कि हम सिर छिपाने के लिए एक कमरा भी नहीं जुटा पाये थे और जब कई-कई दिनों तक बिना खाए एकदम प्रतिकूल परिस्थिति में एक नई पार्टी को गठित करने का संघर्ष करना पड़ा, ... कितने ही वर्षों तक हमें चटाइयों पर सोना पड़ा और वैसे ही कितने जाड़े और गर्मी काटने पड़े। हमारे उस समय के साथी इसकी गवाही देंगे। उन्होंने देखा कि उस समय इसके लिए हमारे मन में किसी तरह की शिकायत नहीं थी। हमने कितने दिन नहीं खाया-किसी से यह बात कहने में भी शर्म आती थी क्योंकि सोचते थे कि खाने का बन्दोबस्त नहीं कर सके, समर्थक नहीं हैं, पाँच पैसे भी चन्दा नहीं जुटा सके, लोगों ने नहीं दिया, यह तो हमारी ही अक्षमता है, इसमें गर्व से कहने की बात क्या है, इसमें त्याग की बात भी क्या है?" आज उन दिनों की बात याद कीजिए, किस तरह पार्टी निर्मित हुई थी। अखबारों ने कॉमरेड शिवदास घोष का वक्तव्य, हमारी पार्टी के संघर्ष की कहानी का कभी प्रचार नहीं किया। हमने उस प्रथम दिन से आज तक जनसाधारण के हाथ से मिला चंदा उठा करके पार्टी चलाई।

आज यहाँ नया दफ्तर बन रहा है, वहाँ एक पुराना दोमंजिला मकान था। भग्नप्राय, जीर्णशीर्ण। उसके एक छोटे से कमरे में 1948 में पहले पहल हमारे दफ्तर का काम शुरू हुआ। उसके बाद दूसरे कमरों में हमारा काम सम्प्रसारित हुआ। मकान टूट पड़ने को था। मालिक मकान की मरम्मत करा ही नहीं रहा था। हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। ऐसी हालत में हमने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों-हमदर्दों से, जनता से मदद की अपील की और उसके आधार पर धनसंग्रह करके पुराना मकान हमने खरीद लिया। उसके बाद यह नया भवन तैयार हुआ। जिन सब कार्यकर्ताओं, समर्थकों, हमदर्दों दोस्तों और लोगों ने इस मकान को खरीदने और नया भवन बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी है, आज के दिन हम उनको धन्यवाद देते हैं। जिन इन्जिनियरों और श्रमिकों ने इस भवन के निर्माण में भूमिका निभाई है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं।

आज हमारी खुशी का दिन है। आज हमारे गौरव का दिन है। साथ ही साथ फिर हम व्यथा के साथ याद करते हैं जिनके उद्देश्य और सपने को दिल में लेकर इस पार्टी का सफर शुरू हुआ था, उनका सपना था पार्टी का अपना खुद का केन्द्रीय दफ्तर हो वे थे कॉमरेड शिवदास घोष। वे ही आज नहीं हैं। दुःख के साथ याद करते हैं कि आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं उनके सुयोग्य सहयोद्धा और अनुगामी कॉमरेड नीहार मुखर्जी, कॉमरेड सचिन बैनर्जी, कॉमरेड प्रीतीश चंदा, कॉमरेड हीरेन सरकार। मौजूद नहीं हैं और भी कई जन, जो दिवंगत हो चुके हैं-कॉमरेड तापस दत्त, कॉमरेड आशुतोष बैनर्जी, कॉमरेड सीतेश दासगुप्ता, कॉमरेड अनिल सेन, कॉमरेड सुकोमल दासगुप्ता, कॉमरेड याकूब पैलान, कॉमरेड कल्याण चौधरी, कॉमरेड बादशाह खान, कॉमरेड प्रतिभा मुखर्जी, कॉमरेड रतन मुखर्जी व और भी असंख्य कॉमरेड। जिनके नाम लिये वे मृत्यु से पहले जानते थे कि मकान खरीद लिया गया है, नया भवन बनाना होगा। इनमें से कई मृत्युशैया पर लेटे हुए ही हालत में थोड़े नया भवन देखने का सपना भी देखा था। आज वे हमारे बीच नहीं हैं। मौजूद नहीं हैं असंख्य शहीद, जिन्होंने कॉमरेड शिवदास घोष के चिन्तन को, झण्डे को उठा कर चलते हुए गोलियों के सामने और हत्यारों के हाथों जान दी है। आज आनन्द और गौरव के दिन हम व्यथा-वेदना के साथ उनको भी याद करते हैं।

आप जानते हैं कि हमारी पार्टी सर्वहारा क्रान्तिकारी पार्टी है। यह दफ्तर भारत के सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्राणकेन्द्र के तौर पर काम करेगा। हमारी पार्टी महान मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष चिन्तनधारा की ताकत से मजबूत हो दुनिया के साम्राज्यवाद-पूँजीवाद, संशोधनवाद, धार्मिक रूढ़िवाद के

(शेष पृष्ठ 7 पर)



निर्भया/ दामिनी गोंगरेप के खिलाफ संघर्ष के दो वर्ष पूरे होने पर महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों व अत्याचार के खिलाफ धरना

नई दिल्ली : 2 वर्ष पहले 'दामिनी' के साथ हुई वीभत्स बलात्कार की घटना और उसके बाद महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ पूरे देश भर में फैल गए आंदोलन को याद करते हुए 16 दिसम्बर को ए.आई.डी.एस.ओ. व ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन के तत्वावधान में जन्तर-मन्तर पर एक धरना दिया गया। महिलाओं व छात्रों ने 'दामिनी' के बलात्कारियों को फाँसी की सजा देने, महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने, अश्लीलता के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने और नशाखोरी के खिलाफ नारे लगाये। वहाँ हुई सभा को जाकिर हुसैन कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्रो. नरेन्द्र शर्मा, ए.आई.डी.एस.ओ. के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड भास्करानन्द, ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सुबोध शर्मा, उपाध्यक्ष एडवोकेट दीपिका जैन, काँ. पुष्पा चमोली और कॉमरेड नीतू खन्ना, सचिवमण्डल सदस्य काँ. सीता सिंह तथा काँ. सन्ध्या विश्वकर्मा, ए.आई.डी.एस.ओ. के कार्यालय सचिव कॉमरेड राहुल सरकार, कॉमरेड कल्पना यादव, श्रेया सिंह व प्रियंका चौरसिया ने संबोधित किया। सभा का संचालन ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य सचिव रितु कौशिक ने किया। धरना स्थल पर 'दामिनी' की याद में एक शोक वेदी बनाकर उस पर पुष्प अर्पित किये गये और मानव श्रृंखला भी बनायी गई।

वक्ताओं ने कहा कि 'दामिनी' पर हुए वीभत्स बलात्कार और हत्या की घटना के बाद जिस प्रकार पूरे देशभर में आंदोलन की लहर चली थी, ऐसा लग रहा था कि इन घटनाओं पर कुछ रोक लगेगी। लेकिन ये घटनाएँ रुक नहीं रही बल्कि लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तमाम दावों के बावजूद प्रशासन महिलाओं पर हो रही इन घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। आज कानून का भय इन अपराधियों के अन्दर से खत्म हो चुका है। पुलिस-प्रशासन द्वारा बरती जा रही कोताही के कारण आज ये घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है कि छोटी बच्चियों पर भी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल इन समस्याओं की जड़ इस पूँजीवादी व्यवस्था ने महिलाओं को जिस प्रकार एक भोग की वस्तु में बदल डाला है, प्रचार माध्यमों से जिस प्रकार नग्नता को खुलेआम परोसा जा रहा है और नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में इन घटनाओं के रुकने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। समाज में अपसंस्कृति का ऐसा जहर घोला जा रहा है कि अन्याय और अत्याचार के प्रति विरोध की मानसिकता ही खत्म की जा रही है। एक ओर तो महान व्यक्तित्वों की जीवनियों को पाठ्यक्रम से निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ स्कूल स्तर से ही यौन शिक्षा के नाम पर छात्रों की नैतिक रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

वक्ताओं ने आम जनता से अपील की कि वे इस सांस्कृतिक पतन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उच्च नीति-नैतिकता व संस्कृति के आधार पर एकजुट हों, महिलाओं पर बढ़ते अपराध की घटनाओं के खिलाफ आगे आएँ और जन संचार माध्यमों द्वारा अश्लीलता फैलाने, महिलाओं के अभद्र चित्रण और नशाखोरी व शराबखोरी के खिलाफ जुझारू जन आंदोलन का निर्माण करें।

महिलाओं पर बढ़ते अपराध, अश्लीलता, नग्नता, नशाखोरी के खिलाफ विरोध मार्च

पटना, बिहार : एआईएमएसएस, ऑल इंडिया डीएसओ तथा एआईडीवाईओ के संयुक्त तत्वावधान में दो वर्ष पूर्व दिल्ली में हुए 'निर्भया' कांड और उसके विरुद्ध हुए संघर्ष से शिक्षा लेने हेतु महिलाओं, युवाओं और छात्रों का एक विरोध मार्च निकाला गया। 'और 'निर्भया' नहीं सहेंगे', 'महिलाओं पर बढ़ते अपराध रोकें', 'अश्लीलता, नग्नता व नशाखोरी पर रोक लगाओ'



आदि गगनभेदी नारे प्रदर्शनकारी वहाँ लगा रहे थे। यह मार्च शहीद-ए-आजम भगत सिंह की मूर्ति के नजदीक से चलकर डाक बंगला चौराहा पर जाकर समाप्त हो गया। इसके पूर्व शहीद-ए-आजम भगत सिंह चौक पर ही एक सभा की गयी।

सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दो साल पहले दिल्ली में 'निर्भया' के साथ जो घटना घटी और उसने जिस कदर संघर्ष किया, वह आज भी हमें ऐसे अपराधों के खिलाफ संघर्ष के लिए आह्वान करती है। केन्द्र और राज्य सरकारें खुल्लमखुल्ला शराब

और सड़ी-गली संस्कृति की दलदल में धकेला जा रहा है। 'निर्भया' को श्रद्धांजलि देते हुए रेप-गोंगरेप की घटनाओं को बढ़ाने में मददगार अश्लीलता फैलाने वाले गीत-सिनेमा-पोस्टर-विज्ञापन, नशाखोरी-शराबखोरी के विरुद्ध संघर्ष करने का सभी ने संकल्प लिया।

वक्ताओं में पटना हाई कोर्ट की एडवोकेट श्रीमती इंदिरा लक्ष्मी, श्री अरविंद महिला कॉलेज की सेवानिवृत्त प्राध्यापिका डा० चित्रा वैश्य, शिक्षिका श्रीमती नम्रता, एआईएमएसएस की राज्य सचिव साधना मिश्रा, अनामिका तथा इंदू कुमारी, ऑल इंडिया डीएसओ पटना जिला



बिक्री को बढ़ावा दे रही हैं। अश्लील गीत, सिनेमा, पोस्टर, वेबसाइट, पोर्नोग्राफी युवाओं के सामने परोस रही हैं। इससे समाज का पूरा वातावरण गंदा हो रहा है। इसी का दुष्परिणाम है कि आज छोटी बच्ची से लेकर वृद्ध महिला तक घर या बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। वक्ताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दो साल गुजरने के बाद भी सरकार वर्मा कमिटी की सिफारिशें लागू नहीं कर सकी, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल पाती। एक तरफ, भूमंडलीकरण-उदारीकरण के दौर में महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ, उन्हें पितृसत्तात्मक समाज में दोगम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। सरकार अच्छी तरह जानती है कि छात्र-नौजवानों के नैतिक-सांस्कृतिक स्तर को बिना नीचे गिराये इस मरणासन्न पूँजीवाद को टिकाये नहीं रखा जा सकता है। इसलिए सरकार जानबूझकर अश्लीलता, नग्नता, नशाखोरी पर रोक नहीं लगाना चाहती है। छात्र-नौजवानों को अनैतिकता

सचिव सरोज कुमार सुमन, निकोलाई शर्मा एवं ऑल इंडिया डीवाईओ के पटना जिला इंचार्ज अनिल कुमार चाँद प्रमुख थे।

प्रतिज्ञा के साथ दी श्रद्धांजलि

अहमदाबाद, गुजरात : 'निर्भया' काण्ड की दूसरी बरसी पर एआईएमएसएस, एआईडीएसओ व एआईडीवाईओ द्वारा गुजरात राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किये गये। अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज के पास निर्भया स्मारक वेदी पर पुष्प अर्पित कर छात्रों, नौजवानों व महिलाओं ने प्रतिज्ञा की कि महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न, प्रताड़ना व अत्याचारों में न तो भाग लेंगे और न ही इनको सहेंगे तथा बलात्कारों व अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष को तेज करेंगे। संगठन ने महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, वर्मा आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू करने व यौन उत्पीड़न-विरोधी कमेटीयों गठित करने की मांग की।



मजदूर हित-विरोधी 'श्रम कानून में संशोधनों' का विरोध

नई दिल्ली : केन्द्र की भाजपा सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों, कदमों व उपायों के खिलाफ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस पर जन्तर मन्तर, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। इसमें ऑल इण्डिया यूटीयूसी के सचिव मण्डल सदस्य कॉमरेड सत्यवान ने अपने भाषण में कहा :

मंच पर उपस्थित हमारे 11 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अध्यक्ष मण्डल, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेतागण और इस संघर्ष के मैदान में आये साथियो,

आप जानते हैं कि आज 5 दिसम्बर को अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस है। इस संघर्ष के मैदान में आने से पहले प्रदेश-प्रदेश में हम सब के साझे सम्मेलन हुए हैं। हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है - इस पर उनमें चर्चा हुई है। देश के कोने-कोने में आज मजदूर जमात, कल-कारखानों के मजदूर, दफ्तर के कर्मचारी, बैंक के क्लर्क, आंगनवाड़ी कर्मी, मिड डे मील कार्यकर्ता, आशा वक्ता, निर्माण श्रमिक, रेल कर्मचारी, बन्दरगाह के मजदूर, सब एक कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के राज के जमाने में जो भयंकर महंगाई, बेरोजगारी, हमारे हकों पर डाकैजनी होती थी, वह आज भी बदस्तूर जारी है। कुछ ही दिनों पहले चुनाव हुए थे। चुनावों में भाजपा के नेताओं, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि वे देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। आज कांग्रेस शासन में नहीं है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और हमारे हकों पर डाकैजनी उसी तरह हो रही है। बात क्या है - अच्छी तरह समझनी है।

दोस्तो, भाइयो और बहनों, जो यह सरकारों की अदला-बदली है, यह सिलसिला हम बार-बार देख रहे हैं। सरकार बदलती है पर नीतियाँ नहीं बदलती हैं - यह बात पल्ले बाध लें। यह जो कहा जाता है कि सरकार सभी की है, यह बात कितनी सही है? गौरतलब है कि अगर सरकार सभी की थी तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ा?

यह सरकार मजदूर वर्ग की परवाह नहीं करती है। चुनाव में पूँजीपति, अरबपति, खरबपति पैसा लगाते हैं और अपनी पसंद की पार्टी और नेता को सत्ता में लाते हैं। हमारे देश में मजदूरों का हक छीनने वाली ये जो नीतियाँ हैं - भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियाँ, ये एक जमाने में कांग्रेस पार्टी लाई थी। लेकिन ये नीतियाँ महज किसी एक पार्टी की नीतियाँ नहीं हैं। अगर ये एक पार्टी की नीतियाँ होती तो उसके बाद बार-बार जो सरकारें आई उन्होंने और वर्तमान भाजपा-नीत सरकार उनको क्यों मानती। ये नीतियाँ पूँजीपति वर्ग की नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ कारपोरेट घरानों की नीतियाँ हैं, ये देशी पूँजीपतियों, एकाधिकारी घरानों और विदेशी लूटरी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच गठबंधन की नीतियाँ हैं। ये हमारी मजदूर वर्ग की नीतियाँ नहीं हैं।

यह जो सरकार आई है, यह पूर्ववर्ती सरकार से भी ज्यादा आक्रामक ढंग से, ताबडतोड़ ढंग से, हमलावर ढंग से मजदूर-कर्मचारियों के उन सब हकों को छीन लेने पर आमादा है जो हक हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने अंग्रेजों के जमाने में लड़ कर हासिल किये थे। यह हरगिज नहीं चलेगा। 67 साल से जो वास्तविकता है, यह सरकार उस वास्तविकता को बदलना चाहती है। कानूनी तौर पर अब तक उसको फैक्टरी माना जाता रहा है जहाँ 20 मजदूर काम करते हैं। आज यह सरकार कहती है कि जहाँ 20 मजदूर काम करते हैं वह फैक्टरी नहीं है। फैक्टरी तो वह है जहाँ 40 मजदूर काम करते हैं। इसे सामने खड़े पहाड़ या पेड़ जैसी वास्तविकता नजर नहीं आती है। यह वास्तविकता को नजरअंदाज कर देना चाहती है। आज तकनीकी और आधुनिक मशीनें जहाँ आ गई हैं, वहाँ कोई एक मशीन 50 आदमियों का काम, कोई 100 आदमियों का काम, कोई 500 आदमियों का काम कर देती है। इस तरह मशीन की मदद से आज 5 आदमी एक छोटे से कमरे में बैठ कर कारपोरेट घरानों का अरबों-खरबों का कारोबार चलाते हैं। सारी दुनियाँ भर में ये घराने लूट मचाते हैं। मेरी राय यह है कि आज 20 मजदूर नहीं बल्कि जहाँ 10 मजदूर काम करते हैं, उसे भी फैक्टरी के दायरे में लाया जाए। मजदूरों के हकों का हनन नहीं चलेगा। आज सरकार कन्ट्रैक्ट कानून को बदलना चाहती है। वह चाहती है कि मजदूरों का कोई रिकार्ड न रहे।



जंतर मंतर पर श्रमिकों के विशाल विश्कोभ धरने को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड सत्यवान

काम करते-करते अगर उसकी मौत हो जाए तो इसका कोई सबूत न रहे और उसे उठा कर गंदे नाले में फेंक दिया जाए ताकि मालिकों को मृतक के परिवार वालों को कोई मुआवजा न देना पड़े। सरकार कानून में ऐसे मजदूर-विरोधी संशोधन लाना चाहती है जिनसे तमाम फैक्ट्रियों और दफ्तरों में ठेकेदारी प्रथा लागू हो जाएगी। ऐसे में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी और ठेका मजदूरों को पूरा वेतन नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों में भी गेस्ट फैकल्टी, ठेका मजदूर, अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारी, ठेके पर लगे डाक्टर, ठेके पर लगी नर्स, ठेके पर लगे अधिकारी होंगे। यह नहीं चलेगा - हम यही कहने यहाँ आये हैं।

दोस्तो, जब कोई सरकार आती है तो कहा जाता है कि संघर्ष की नई शुरुआत हुई है और जब सरकार चली जाती है तो उसके साथ ही संघर्ष में भी एक नया मोड़ आ जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार आये और जाएं, पर हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए और एक मजिल से दूसरी मजिल पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। हम कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ें। हमें लड़ने का कोई शोक नहीं है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमारे हकों को छीना जाता है। हमारी गर्दन पर छुरी रख दी जाती है। हमारा खून चूसा जाता है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज यह सरकार खून चूसने की उसी कार्रवाई को और भी तेज कर रही है तो हमारी लड़ाई पहले की लड़ाइयों से भी ज्यादा संगीन, ज्यादा जोरदार और ज्यादा सर्वव्यापक होनी चाहिए। यहाँ रेलवे मेन्स यूनियन के हमारे साथी हरभजन सिंह सिद्धू कह रहे थे कि रेलवे कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना चाहते हैं। मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूँ। वह फैसला हम सभी का फैसला होना चाहिए। हम हिन्दुस्तान के कोने-कोने में तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि हमारे हकों की गारण्टी कानून में नहीं हो जाएगी। यह संसद कुछ लोगों की बनाई हुई नहीं है। यह संसद हिन्दुस्तान की जनता ने अंग्रेजशाही और राजा-महाराजाओं के खिलाफ लड़ कर बड़ी कुर्बानियों से बनाई है। इस संसद में मजदूरों के खिलाफ अत्याचारी कानून नहीं बनने दिये जाएंगे। इसलिए हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ायें। यही मेरा कहना है। डिसेन्ट वर्क, डिसेन्ट वेज, यानी बेहतर काम का बेहतर वेतन, यूनियन बनाने के हमारे अधिकार, शोषण-अन्याय के खिलाफ लड़ने के हमारे अधिकार, अपने हक लेने के लिए सामूहिक रूप से कार्रवाई करने के हमारे अधिकार को यह सरकार मान्यता दे। हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इसी

श्रम कानूनों में बीजेपी सरकार के मालिकपरस्त व मजदूर-विरोधी संशोधनों के खिलाफ दीर्घस्थायी संयुक्त आन्दोलन गठित करें

— शंकर साहा

केन्द्र की बीजेपी सरकार के श्रम कानूनों में मालिक परस्त और मजदूर-विरोधी संशोधनों, कदमों और उपायों के खिलाफ 11 प्रमुख केन्द्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त आह्वान पर 5 दिसम्बर को अखिल भारतीय विरोध दिवस पर देश के सभी राज्यों की राजधानियों में मजदूर-कर्मचारियों के विश्कोभ धरने के प्रसंग में एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर साहा ने निम्नलिखित बयान दिया :

“केन्द्र की बीजेपी सरकार ने मालिक वर्ग के स्वार्थ में एकतरफा तौर पर औद्योगिक-विवाद कानून, फैक्टरी कानून, कन्ट्रैक्ट लेबर कानून, अप्रेंटिस कानून, संक्षेप में समग्र तौर पर श्रम कानूनों में संशोधन करने की जो पहलकदमी की है उसके खिलाफ देश की 11 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 5 दिसम्बर को दिल्ली से लगते राज्यों के मजदूर-कर्मचारियों की उपस्थिति में सफल धरने का कार्यक्रम लिया गया। ये सुधार-संशोधन लागू होने से 300 मजदूर काम करते हैं ऐसे उद्योगों में बेरोकटोक छंटनी चलेगी। संक्षेप में देश में श्रम कानून कहने को कुछ नहीं रहेगा और मालिकों को छंटनी और लूट की खुली छूट मिल जाएगी। पिछले 7 दशक से लम्बे संघर्षों और कुर्बानियों से देश के मजदूर वर्ग जितने भी कानून उनके पक्ष में प्रतिष्ठित करवा पाया था, सत्ता में बैठने के मात्र कुछेक महीनों में ही मोदी सरकार मालिक वर्ग के स्वार्थ में उनको छीन लेने का निर्लज्ज कदम उठा रही है।

इस भयावह परिस्थिति में केवल एक दिन के सफल धरना और विश्कोभ सभा ही नहीं, बल्कि आगामी दिनों में हड़ताल सहित जो दीर्घस्थायी एकजुट आन्दोलन गठित करते जा रहे हैं उसे हर तरह से सफल करने के लिए हम सभी तबकों के मेहनतकश लोगों से आह्वान करते हैं।”

बात के लिए हम सब एक हैं। लड़ाई के लिए एक हैं। अपने हकों को बचाने के लिए एक हैं। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपके बीच नारा लगाता हूँ इन्कलाब जिन्दाबाद!

जंतर मंतर पर साम्प्रदायिकता-विरोधी जुलूस

नई दिल्ली : 6 दिसम्बर, 1992 को बीजेपी व संघ परिवार ने मध्ययुगीन बर्बर ध्वंसलीला कर एक काला अध्याय रचा था। बाबरी मस्जिद सिर्फ मुस्लिमों का धर्मस्थल ही नहीं थी, बल्कि प्राचीन स्थापत्य कला का नमूना और ऐतिहासिक महत्व का स्मारक थी। इसको तोड़ कर बहुत ही धिनौना कांड किया था जिसके लिए सभी सदबुद्धिसम्पन्न तर्कशील लोग इसे काला दिन कह कर धिक्कारते हैं। इस दिन जंतर मंतर पर हुई संयुक्त विरोध सभा में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभा को राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल व राज्य सचिवमंडल सदस्य कॉ. रमेश शर्मा, सीपीडीआरएस की ओर से प्रो. नरेन्द्र शर्मा ने सम्बोधित किया।



अनिवार्य तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत पढ़ाने के बारे में एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष का बयान

केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य करने के भाजपा सरकार के अचानक एवं मनमाने फैसले को अभिभावक एवं शिक्षाविद उद्विग्नता से देख रहे हैं। सरकार इस फैसले को विस्तार देकर अन्य स्कूलों में भी लागू करने की मंशा पहले ही प्रकट कर चुकी है। छात्र हितों को धूल में मिलाते हुए वह सत्र के बीच में यह बदलाव ला रही है। इस चाल की हम भर्त्सना करते हैं और अपना कड़ा विरोध जताते हैं/ दर्ज करते हैं। स्कूल स्तर पर किस भाषा या किन भाषाओं को अनिवार्य तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए—इसका चयन तीन विचारणीय बातों से मार्गदर्शित होता है। पहले तो, यह एक ऐसी भाषा हो जो उच्च ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की प्रगतियों के मुख्य द्वार के तौर पर काम करती हो। दूसरे, यह विभिन्न भाषा-भाषी लोगों में आपस में संवाद करने की भाषा हो। तीसरे, इस भाषा का ज्ञान विद्यार्थियों को उनके परवर्ती पेशेवर जीवन में आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला हो। संस्कृत इन तीनों कसोटियों पर खरी नहीं

उतरती। यह न तो आधुनिक विज्ञान या दर्शन की वाहक है, न ही समाज में किसी भी हिस्से के लोगों के बीच संवाद करने की भाषा है और न ही रोजगार के बाजार में संस्कृत का ज्ञान छात्रों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा, दूसरे धर्मों के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ने के लिए विवश किया जाता है तो इससे असंतोष पैदा होगा और विभिन्न धार्मिक समुदायों में अनचाहा तनाव पैदा करेगा। इसलिए किसी आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा के स्थान पर संस्कृत को अनिवार्य तौर पर पढ़ाये जाने से शिक्षा के हितों को नुकसान पहुँचेगा अपितु समाज के लिए भी इसके विपत्तिपूर्ण दुष्परिणाम होंगे। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस नीति का विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि संस्कृत हमें नापसन्द है बल्कि हमारा यह मानना है कि किसी भी भाषा का ज्ञान हमेशा ही एक वांछित योग्यता है। कोई विद्यार्थी यदि किसी भाषा को सीखना चाहता है तो एक वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनने की उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए।

यह नीति एक खतरनाक अशुभ संकेत देती है क्योंकि हमारा यह विश्वास है कि यह नीति भाजपा-संघ परिवार द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के भगवाकरण करने की जघन्य चाल का एक हिस्सा है। विज्ञानसम्मत मन और जनतांत्रिक मूल्यों को तहस-नहस करने के उद्देश्य से वे हर तरह के पुराने दकियानूसी, रूढ़िवादी विचारों को प्रसारित कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वे सांस्कृतिक फासीवाद कायम करना चाहते हैं। गीता का एक राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का प्रस्ताव उनके इसी अनिष्टकारी मंसूबे का हिस्सा है। वे बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को उकसा रहे हैं और साम्प्रदायिक भावनाओं व भ्रातृघाती झगड़ों को भड़का रहे हैं ताकि मेहनतकश लोगों की एकता टूट जाए और पूँजीवाद-विरोधी वर्ग संघर्ष और जन आन्दोलन छिन्न-भिन्न हो जाएं। इस खतरे से हम देशवासियों को चौकस रहने और भाजपा व संघ परिवार की फूटपरस्त साम्प्रदायिक राजनीति के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ने की अपील करते हैं।

सरकार की जनविरोधी नीतियों के ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

पटना, बिहार : एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई एमएल-लिबरेशन, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक इत्यादि देश के छह प्रमुख वामपंथी दलों ने जनजीवन पर हो रहे हमलों, केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों, आसमान छूती महंगाई तथा साम्प्रदायिकता-फिरकापरस्ती के खिलाफ 15 दिसम्बर को राजधानी पटना में संयुक्त एकदिवसीय धरने का कार्यक्रम लिया।

गांधी मैदान के समीप शहीद भगत सिंह चौक पर आयोजित धरने को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमिटी के वरिष्ठ सदस्य अरूण कुमार सिंह तथा राज्य कमिटी सदस्य व पटना जिला सचिव साधना मिश्रा समेत सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई एमएल-लिबरेशन तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने संबोधित किया। धरने का संचालन एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य सचिव कॉमरेड शिव शंकर समेत सीपीआई, सीपीआई (एम), सीपीआई एमएल-लिबरेशन, तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं को लेकर बने अध्यक्ष मंडल ने किया।

मुजफ्फरपुर, बिहार: छह वाम दलों के साझा राष्ट्रीय प्रतिवाद अभियान के तहत 9 दिसम्बर को समहरणालय परिसर में महाधरने का आयोजन किया गया।

धरने की अध्यक्षता एसयूसीआई (सी) के जिला सचिव अर्जुन कुमार, भाकपा (माले) के शत्रुघ्न सहनी, सीपीआई के जिला सचिव अजय सिंह, सीपीआई (एम) के अब्दुल गफफार एवं अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक के हबीब अंसारी की अध्यक्षमंडली ने की। एसयूसीआई (सी) के राज्य कमिटी सदस्य कॉ. अशोक कुमार सिंह ने महंगाई खत्म करने व काला धन वापस लाने में केन्द्र सरकार की वायदा खिलाफी बताया। कॉ. लालबाबू महतो ने कहा कि आरएसएस व हिन्दुत्व की विचारधारा की घुसपैठ तेजी से हो रही है। इससे साम्प्रदायिक ताना-बाना टूट रहा है। कॉ. काशीनाथ सहनी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता जतायी। मो. इदरीश ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई से न केवल विदेशी कम्पनियों का मुनाफा बढ़ेगा बल्कि देश के बीमाधारकों का भविष्य देशी-विदेशी कम्पनियों के हाथों में होगा। एसयूसीआई (सी) के नरेन्द्र राम, भाकपा माले के सकल ठाकुर, सूरज कुमार सिंह, रामबालक सहनी, टुन्ना झा, सीपीआई (एम) के रामपुकार सहनी, सुन्देश्वर सहनी, नमिता सिंह, रामलाल सिंह, राजेन्द्र राय, सीपीआई के राज्य परिषद सदस्य विद्या सिंह, चन्देश्वर चौधरी, एसएस मिश्रा, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक के जिन्देश्वर झा आदि ने भी सभा को संबोधित किया। अंत में वाम दलों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा।

दुर्ग, छत्तीसगढ़ : 12 दिसम्बर को 4 वामपंथी पार्टियों एसयूसीआई (कम्युनिस्ट), सीपीआई (एम), सीपीआई और सीपीआई (एमएल लिबरेशन) द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों व साम्प्रदायिकता के खिलाफ रायपुर में संयुक्त धरना-प्रदर्शन किया गया। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. विश्वजीत हारोडे ने धरने को सम्बोधित किया।

भिवानी (हरियाणा) : वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने केन्द्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ 16 दिसम्बर को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, हरियाणा के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त, भिवानी को सौंपा। प्रदर्शनकारी नेहरू पार्क के समक्ष एकत्रित हुए और वहाँ से जुलूस की शकल में लघु सचिवालय पहुँचे। प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेता धर्मवीर कुंगडू व जिला सचिव दयानंद पूनिया तथा एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव रामफल व धर्मवीर सिंह ने किया।

नेहरू पार्क में हुई विरोध सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की ओर से जिला सचिव कॉ. रामफल व धर्मवीर सिंह और सीपीआई (एम) की तरफ से जिला सचिव दयानंद पूनिया और धर्मवीर कुंगडू ने सम्बोधित किया।

11 से 18 दिसम्बर तक हरियाणा के बाकी सभी जिलों में भी वामपंथी पार्टियों का साझा आन्दोलन चला और जिला मुख्यालयों पर धरने-प्रदर्शन हुए। (शेष पृष्ठ 8 पर)

पटना



मुरादाबाद



भिवानी



यह दफ्तर क्रान्ति के...

(पृष्ठ 3 का शेष)

खिलाफ और हर तरह की भाववादी प्रतिक्रियाशील सोच के खिलाफ जो संघर्ष करती आ रही है और देश-देश में जोरदार साम्यवादी आन्दोलन गठित करने के क्षेत्र में हमारी पार्टी जो भूमिका अदा करती जा रही है—उसी रास्ते पर अडिग रहने का संकल्प हम दोबारा व्यक्त करते हैं। यह दफ्तर उस महान संघर्ष के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केन्द्र के तौर पर काम करता जाएगा। हम इस देश की सरजमीन पर पूँजीवाद को उखाड़ फेंक कर समाजवाद कायम करने के लिए जिस क्रान्तिकारी संघर्ष में लगे हुए हैं और उस मकसद को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग, किसान, सर्वहारा वर्ग, मध्यम आयवर्गीय जनता, छात्र-नौजवान-महिलाओं के जीवन की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग पर क्रान्तिकारी लाइन के आधार पर और भी उन्नत नैतिकता की बुनियाद पर मजबूत हो कर जो वर्ग संघर्ष और जनआन्दोलन गठित कर रहे हैं, यह दफ्तर उन संघर्षों को गठित करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

हमारे देश में फासीवाद का जो खतरा और भी भयावह रूप में दिखाई दे रहा है, धार्मिक रूढ़िवाद, साम्प्रदायिकता जिस खतरनाक ताकत के तौर पर सिर उठा रही है, उसके खिलाफ भी चौतरफा संघर्ष गठित करने के क्षेत्र में हमारा यह दफ्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता जाएगा। सर्वहारा के महान चिन्तनकार कॉमरेड शिवदास घोष हमें बार-बार कह गये हैं कि क्रान्तिकारी राजनीति की मर्मवस्तु उन्नत नैतिकता का स्तर होता है। वे कह गये हैं कि हमारे देश में शोषक पूँजीपति वर्ग जनता के, खास कर छात्र-नौजवानों के नैतिक बल, इन्सानियत को खत्म करने की साजिश रचता जा रहा है। ताकि इस देश में कोई नया खुदीराम बोस, बाघा जतीन, सूर्य सेन, प्रीतिलता, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान पैदा न हो सके। एक भयंकर हमला जारी है। वे कह गये हैं कि हमें जड़ों से काट दिया गया है। इसलिए उन्होंने बार-बार आह्वान किया था कि हम इस देश के पुराने जमाने के नवजागरण के मनीषियों और आजादी आन्दोलन के क्रान्तिकारियों के जीवन-संघर्ष का अध्ययन करें, उनके जीवन से मूल्यवान सम्पदा हासिल करें। दुनिया के विभिन्न देशों के मनीषियों और क्रान्तिकारियों के जीवन से मूल्यवान सम्पदा हासिल करें। यह हमारी पार्टी और जनसंगठनों के लिए एक जीवन्त संघर्ष है। इस संघर्ष को चलाने के मामले में भी हमारा यह दफ्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता जाएगा—यही दृढ़ इरादा हम एक बार फिर व्यक्त कर रहे हैं। पार्टी के शुरूआती जमाने में कितने कठिन संघर्ष के जरिये कॉमरेड शिवदास घोष ने इस पार्टी का गठन किया था, यह आप सुन चुके हैं। आज पार्टी बढ़ रही है, भारत में सर्वत्र पार्टी फैलती जा रही है। हजारों हजार मजदूर-किसान पार्टी के झण्डे के नीचे एकजुट हो रहे हैं। देश के कोने-कोने में बहुत सारे जुझारू छात्र-नौजवान और महिलाएं कॉमरेड शिवदास घोष से प्रेरित हो कर इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। पार्टी की ताकत बढ़ रही है और बढ़ेगी।

कल में जा रहा हूँ बांग्लादेश। वहाँ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष चिन्तनधारा के आधार पर एक शक्तिशाली क्रान्तिकारी पार्टी गठित हुई है। वे वहाँ कन्वेंशन कर रहे हैं। उन्होंने हमारी पार्टी को आमन्त्रित किया है। पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मैं जा रहा हूँ। विभिन्न देशों में भी कॉमरेड शिवदास घोष के क्रान्तिकारी चिन्तन को लेकर चर्चा चल रही है, साधना चल रही है। यह एक ऐतिहासिक आन्दोलन का रूप ले रही है। पार्टी बढ़ रही है, पार्टी और भी बढ़ेगी। और भी दफ्तरों की जरूरत पड़ेगी। मैं अखिरी बात कहने से पहले कॉमरेड शिवदास घोष की एक और उक्ति देकर ही अपना वक्तव्य खत्म करूँगा, मेरा अपना खुद का विवेक जगाने के लिए, आपका विवेक जगाने के लिए। ये बातें मानो पीढ़ी दर पीढ़ी, हम भी जब नहीं रहेंगे, बाद में जो आयोगें उनके विवेक में मानो जीवन्त शक्ति के तौर पर काम करती जाएँ। इसलिए मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ—'पहले पहल जब यह पार्टी शुरू हुई तब हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। रुपया-पैसा नहीं था, लोग साथ नहीं थे। अनेक ही हमारी बात सुन कर कहते थे कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन पार्टी बनाना आसान है

रेल यात्रियों, खास कर महिलाओं, बच्चों व छात्राओं की सुरक्षा की गारण्टी की उठाई मांग

मुरादाबाद (उ.प्र.): ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिला कमेटी मुरादाबाद ने 30 नवम्बर को रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पर जोरदार प्रदर्शन किया और रेल यात्रियों, खास कर महिलाओं, बच्चों व छात्राओं की सुरक्षा की गारण्टी करने, दिल्ली से मुरादाबाद इएमयू चलाने, महिलाओं कोच बढ़ाने, व डिब्बे का रंग बदलने, स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि की मांग उठाई। इसके अलावा, 15 नवम्बर को दिल्ली से इण्टर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन में मुरादाबाद लौट रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. हरकिशोर सिंह व एआईयूटीयूसी की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्या कां. कमलेश चहल को जान से मारने का प्रयास करने वाले बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन स्टेशन सुपरिटेण्डेंट के द्वारा माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार को भेजा। इस दौरान स्टेशन परिसर में हुई सभा को हरकिशोर



सिंह, मौ. गौरी, विनोद विग, रूबी बच्चो, मेजू मेहता, कमलेश चहल, कविता सिंह, विजयपाल सिंह, भावना सिंह, माया राजपूत, लिपि, रीना, स्वीटी, श्यामसुन्दर, मौ. गौरी, आदि ने सम्बोधित किया। संगठन का प्रतिनिधि मण्डल 18 नवम्बर को डी.आर.एम. मुरादाबाद व एस.पी. रेल मुरादाबाद से मिला और बदमाशों को पकड़ने की मांग की।

4 वर्षीय छात्रा के साथ की गई दरिदगी के खिलाफ रोष प्रदर्शन



मुरादाबाद (उ.प्र.): लिटिल एंजिल्स पब्लिक स्कूल, बुद्ध विहार, मुरादाबाद के प्रबंधक द्वारा नर्सरी क्लास की 4 वर्षीय छात्रा के साथ की गई दरिदगी के खिलाफ एआईडीवाईओ, एआईडीएसओ तथा एआईएमएसएस ने संयुक्त रूप से 12 नवम्बर को स्कूल के गेट पर एक विशाल सभा की। सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया जो 14 नवम्बर को जिलाधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन कर डी.एम. को सौंपा गया।

प्रस्ताव में आरोपी स्कूल प्रबंधक के खिलाफ फास्ट ट्रेक कोर्ट में मुकदमा चलाकर नए कानून के तहत दण्डित करने, शिक्षा, सुरक्षा की गारण्टी करने, लिटिल एंजिल्स स्कूल में पढ़ाई कर रहे सभी बच्चों की फीस वापिस करने व बिना एडमिशन शुल्क के अन्य स्कूल में प्रवेश दिलाने, घटना वाले स्कूल को तत्काल बन्द कराने, बिना मान्यता के चल रहे अवैध स्कूलों के मालिकों या प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। प्रशासन द्वारा स्कूल को तत्काल बन्द करा दिया गया। सभी बच्चों के प्रवेश निःशुल्क अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में करा दिए गए। पीड़ित परिवार को हर प्रकार की सहायता व सुरक्षा देने की घोषणा की गई। संगठन द्वारा उठाई मांगें पूरी हो जाने से आन्दोलन की जीत हुई। इस आन्दोलन का नेतृत्व एआईडीवाईओ के जिला सचिव मौ. गौरी उपाध्यक्ष बबीता सिंह, अध्यक्ष विनोद विग, एआईडीएसओ की जिला अध्यक्ष ऋतु, एआईएमएसएस की जिला सचिव भावना सिंह व कमलेश चहल आदि ने किया।

जीवन की ज्वलंत मांगों को लेकर निकाला जुलूस

लालगंज (बिहार): 28 नवम्बर को वाम मोर्चा के किसान खेत-मजदूर संगठनों द्वारा लालगंज प्रखण्ड कार्यालय पर धरना दिया गया। सभा का संचालन तीन सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल केकेएमएस के वैशाली जिला संयोजक डॉ. राजेन्द्र शर्मा, भाकपा के अंचल सचिव डॉ. इन्दुभूषण सिंह विनय एवं भाकपा काले के प्रखण्ड प्रभारी डॉ. सुरेश सिंह ने किया। सभा को एस.यू.सी.आई.(सी) के अंचल सचिव डॉ. राजेन्द्र शर्मा, भाकपा के अंचल सचिव डॉ. इन्दुभूषण सिंह विनय, भाकपा माले के प्रखण्ड प्रभारी डॉ. सुरेश सिंह, डॉ. नवल किशोर श्रीवास्तव, एसयूसीआई (सी) के डॉ. मिस्टर पासवान आदि ने सम्बोधित किया।

तत्पश्चात 22 सूत्री मांगपत्र प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को सौंपा गया। सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने, धान की खेती करने वाले किसानों को फसल में पानी न पाने की

स्थिति में क्षतिपूर्ति कराने, ग्राम पंचायत सिरसा वीरन के पंचायत सचिव का स्थानान्तरण अविलम्ब करने, चौरों से जल निकासी की व्यवस्था कराने, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, उसमें बिचौलियों का हस्तक्षेप बन्द कराने, फर्जी बिजली बिल का जल्द निष्पादन कराने, नीलगाय एवं जंगली सूअर से लालगंज क्षेत्र को मुक्त कराने की मांगें शामिल थीं।



क्या? कोई नेता नहीं, प्रेस-पब्लिसिटी नहीं। यह असम्भव बात है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनको केवल एक ही जवाब देता हूँ—हाँ, मान लिया कि नहीं होगा। लेकिन क्या करूँ बताइये? गुलाम बन जाऊँ? दलाली करने लग जाऊँ? जमीर बेच दूँ? या जो समझता हूँ वह न करके दूसरी तरह का आचरण करूँ? यह मैं नहीं कर पाऊँगा। इफ आई डाई स्टार्विंग इन दि स्ट्रीट, आई शैल डाई विद ऑनर रेंजिंग माई हैड हाई!...मुझे गोली से मार दिया जाए, मैं जानता हूँ हो सकता है कि मुझे भूखा रह कर मरना पड़ेगा, भूख से मर रहा हूँ कि नहीं इसकी खबर भी हो सकता है कि कोई न लेने आये, लेकिन क्या करूँ? इस कोशिश में फिलहाल नाकाम भी हो सकता हूँ। सोच लूँगा मैं नहीं कर पाया, यह मेरी अक्षमता थी। अक्षमता की शर्म एक तरह की होती है, लेकिन जमीर बेचना अपराध है। सोचूँगा नहीं कर पाया, लेकिन

सिर नहीं झुकाया। भूखों मर गया, लेकिन क्या कुछ भी नहीं किया? सभी क्रान्तिकारी जान जायें कि वह भूखों मर जाने के द्वारा भी कह गया कि इस व्यवस्था से कुछ नहीं होगा। इस शोषणमूलक व्यवस्था को क्रान्ति के द्वारा पलट डालना होगा। उनकी यह अपील सच न जाये। एक-दो आदमी करते-करते लोग जुड़ने लगते हैं, अपील पर प्रत्युत्तर देने लगते हैं। 1967 में कॉमरेड घोष की यह ऐतिहासिक उक्ति है। आप जानते हैं उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। उनकी लड़ाई सफल हुई। पार्टी बढ़ रही है, बढ़ेगी और इसी रास्ते हम इस देश के करोड़ों लोगों का शोषण से मुक्ति का जो संघर्ष है, जो कॉमरेड शिवदास घोष का सपना था उसे हम सब एक साथ मिल कर सफल कर पायेंगे, इस बात पर मैं पक्का यकीन करता हूँ। यही कह कर मैं दफ्तर का उद्घाटन कर रहा हूँ।

गणतंत्र दिवस समारोह पर अमेरिकी राष्ट्रपति को बुलाने के खिलाफ एसयूसीआई (सी) के महासचिव ने वाम दलों को लिखा पत्र

महासचिव, सी.पी.आई., सी.पी.आई.(एम), फारवर्ड ब्लॉक, आर.एस.पी., सी.पी.आई.(एम एल)-लिबरेशन प्रिय कॉमरेड,

आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत सरकार ने 26 जनवरी, 2015 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान खास मेहमान के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को आमंत्रित किया है। वह अमेरिकी साम्राज्यवाद का सरगना है, मानवजाति का घृणित शत्रु है, जिसने दशकों से फौजी हमले का सहारा लेकर और षडयंत्रकारी तिकड़मों के जरिये बहुत से देशों की सार्वभौमिकता और स्वतंत्रता पर खुल्लमखुल्ला हमला किया है; धार्मिक कट्टरतावादी और नस्ली दंगे भड़का कर देशों के बीच युद्ध भड़काये और इस तरह बच्चों व बुजुर्गों सहित लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, महिलाओं पर पाशविक बलात्कार करवाये, गांव-शहरों को खण्डहरों में तब्दील कर डाला और विभिन्न देशों के संसाधनों को लूटा है। इन भयंकर हमलों और तबाही के गवाह न केवल हिरोशिमा और नागासाकी, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, कोरिया हैं बल्कि आज के दिन इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया सहित पूरे मध्य पूर्व, तमाम अरब दुनिया के साथ-साथ लैटिन अमेरिकी देश भी अमेरिकी बर्बरता, दादागिरी और लुटमार के जीते-जागते सबूत हैं।

जाहिर है कि सिर्फ दक्षिणी एशिया में ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व, अरब दुनिया व अन्यत्र भी साम्राज्यवादी दबदबा कायम करने के अपने प्रयास में भारत की पूँजीवादी राजसत्ता आर्थिक-व्यापारिक-राजनयिक-सामरिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपने गठजोड़ को लगातार विस्तारित और मजबूत करती जा रही है।

हमारा मानना है कि साम्राज्यवादी अमेरिका के राष्ट्रपति को आमंत्रित करके केन्द्रीय सरकार भारत के साम्राज्यवाद-विरोधी स्वतंत्रता संग्राम की शानदार परम्परा और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, शहीद-ए-आजम भगत सिंह सरीखे इसके महान बहादुर योद्धाओं और शहीदों का अपमान कर रही है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत के लोग भारत सरकार के इस घोर नाजायज फैसले का कर्तई समर्थन नहीं कर सकते हैं। इस निमंत्रण को वापिस करने की मांग पर देशव्यापी जोरदार आन्दोलन गठित करना हमारा फर्ज बनता है।

हमारा प्रस्ताव है कि इस मामले पर चर्चा करना और एक्शन का व्यापक कार्यक्रम तय करने के लिए 6 वामपंथी पार्टियों के केन्द्रीय नेताओं की बैठक तुरंत बुलाई जाए।

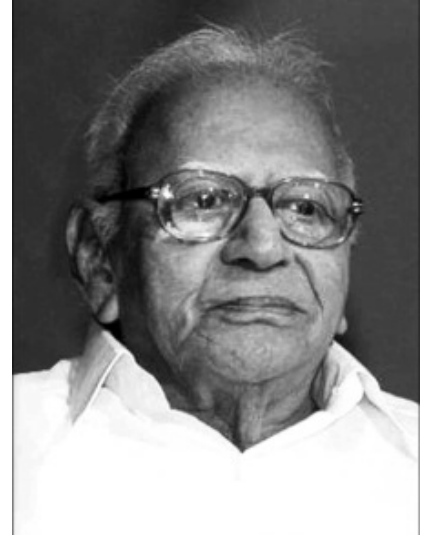
हमें उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित

आपका
प्रभाष घोष

जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर की मृत्यु पर एसयूसीआई(सी) ने प्रकट किया गहरा शोक

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 4 दिसम्बर को जारी एक बयान में कहा :

4 दिसम्बर के दिन श्रद्धेय जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर की मृत्यु पर पार्टी की ओर से हम भारी दिल से शोक प्रकट करते हैं। उनकी मृत्यु से जो क्षति हुई है वह अपूरणीय है। धर्मनिरपेक्ष जनवादी मूल्यों-सिद्धियों के सर्गम अनुसरणकर्ता जस्टिस अय्यर ने अपने पेशेवर व सार्वजनिक जीवन, दोनों में ही जीवन भर दबे-पिसे व सुविधाओं से वंचित लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए लगातार भरसक प्रयास किये, वे उनके हित-उद्देश्यों के लिए लड़े और सत्ताधारियों की ओर से गरीबों व मजदूरों को उनके जायज हक-हकूकों से महरूम करने की हर कुचैप्टा के खिलाफ डट कर खड़े हुए। वे एक नामी-गिरामी न्यायविद थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश के तौर पर बड़ी भारी प्रतिष्ठा पायी, उनके विचार प्रगतिशील और रैडिकल थे और लोगों की मांगों को केन्द्र करके हुए जनवादी जनआन्दोलनों के अगले मोर्चे पर रहे। शिक्षा बचाओ आन्दोलन, साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन, साम्प्रदायिकता-रूढ़िवादिता के खिलाफ आन्दोलन, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ आन्दोलन, नागरिक व जनवादी अधिकारों की रक्षा, बहाली व विस्तार के लिए आन्दोलन की अगुवाई करने में उन्होंने जो नेतृत्वकारी व प्रेरणादायक भूमिका अदा की, उसे हम बड़ी कृतज्ञता के साथ याद करते हैं। जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, तब हमारी पार्टी ने उनको तहेदिल से समर्थन दिया था।



उनकी मृत्यु से देश ने एक सत्यनिष्ठ और बहुत बड़ी हस्ती को खो दिया है जिनको तमाम बुराइयों व अन्याय के खिलाफ लड़ाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए सदा याद किया जाएगा। हम शोकसंतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हैं।

उबर कैब बलात्कार के खिलाफ ए.आई.डी.एस.ओ. तथा ए.आई.एम.एस.एस. द्वारा पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन

दिल्ली : 6 दिसम्बर की रात में 'उबर' कैब के एक ड्राइवर द्वारा एक 27 वर्षीय महिला के साथ किए गए बलात्कार की शर्मनाक घटना के खिलाफ 8 दिसम्बर को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन व ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आई.टी.ओ. स्थिति दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। महिलाएं व छात्र पुलिस मुख्यालय पर इकट्ठे होकर दोषी ड्राइवर को उदाहरणमूलक सजा देने तथा कैब कम्पनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे।

वहीं पर हुई सभा को ए.आई.एम.एस.एस. की दिल्ली राज्य सचिव रितु कौशिक, उपाध्यक्ष सीता सिंह, आशा देवी, ए.आई.डी.एस.ओ. के राज्य अध्यक्ष भास्करा नन्द, सचिव प्रशान्त कुमार, राज्य कमेटी सदस्य रवि कुमार व अन्य नेताओं ने सम्बोधित करते हुए कहा कि यह घटना एक बार फिर



दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गम्भीर सवाल खड़ा करती है। तमाम दावों के बावजूद प्रशासन महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। 'उबर' कैब कम्पनी द्वारा उन नियमों का घोर उल्लंघन किया गया जिन्हें जनपरिवहन में होना चाहिए था। इसके बावजूद कम्पनी द्वारा इस टेक्सी को चलाया जाना न केवल कैब कम्पनी के मालिक को आरोप के दायरे में लाता है बल्कि इस अनियमितता के लिए यातायात प्रशासन की भी जवाबदेही बनती है। इस घटना में जिस प्रकार ड्राइवर ने उस महिला को धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर इसके बारे में किसी को बताने के अंजाम के तौर पर मार डालने का डर दिखाकर उसे घर पर छोड़ कर भाग गया, यह इस बात को साबित करता है कि इन अपराधियों में आज कानून का भय खत्म हो चुका है। पुलिस-प्रशासन द्वारा बरती जा रही कोताही के कारण ये घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं।

वक्ताओं ने आम जनता से अपील की कि वे एकजुट हों, महिलाओं पर बढ़ते अपराध की घटनाओं के खिलाफ सामने आएँ और जन संचार माध्यमों द्वारा अश्लीलता फैलाने, महिलाओं के अभद्र चित्रण, नशाखोरी व शराबखोरी के खिलाफ जुझारू जन आंदोलन का निर्माण करें।



(पृष्ठ 6 का शेष) संयुक्त वामपंथी आन्दोलन में देश भर में सड़कों पर उतरे लोग